LOK SABHA

Wednesday, November 22, 1972

Agrahayana 1, 1894 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reduction in Cement Quota for Delhi

*122. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:

SHRI D. P. JADEJA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether cement quota of the Union Territory of Delhi has been reduced drastically; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछने के पूर्व आपकी आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार वस्तुस्थिति की जानकारी न रख कर सीधे नकारात्मक उत्तर दे कर अपने को बचाना चाहती है नियंत्रित वस्तुओं के सम्बन्ध में। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली शहर के अन्दर 20 रुपये, 22 रुपये प्रति बैग. . . . .

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि नो सर, तो फिर यह प्रश्न कहां से आता है ?

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: उसी के बारे में मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: एप्लीमेंट्री सवाल में इन्फार्मेशन देते नहीं लेते हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जब सही उत्तर नहीं आता है तो वस्तुस्थिति की जानकारी दे कर उस का उत्तर लेना मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य का कर्त्तव्य है और इस कर्त्तव्य के मातहत मैं यह पूछ रहा हूं क्योंकि सरकार वस्तुस्थिति को जानकर छिपाना चाहती है। इसीलिए मैं इस प्रश्न को पूरक प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूं।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली शहर के अन्दर 20 रुपये, 22 रुपये प्रति बोरे की दर से सीमेंट काले बाजार में बिक रही है ? इस के साथ साथ क्या सरकार बतायेगी कि पिछले साल कितना सीमेंट इस शहर के अन्दर दिया गया . . .

अध्यक्ष महोदय : यह इस से पैदा नहीं होता। आप कैसे यह सवाल कर रहे हैं ?

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं, आप जरा सुनें। यह इन्होंने कहा है कि कमी नहीं की गई है. . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप यह गलत कर रहे हैं। आप को प्रश्न पूछना है तो सीधे पूछें।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मैं इसी के आधार पर पूछ रहा हूं कि पिछले साल कोटे के अन्दर दिल्ली शहर को कितना सीमेंट दिया था और इस साल कितना दिया है और कितनी डिमांड थी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका सेपरेट क्वेश्चन आप कीजिये ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मैं यह कह रहा हूं कि जितनी उन की डिमांड थी उस के मुताबिक उन्होंने नहीं दिया है और कमी की है । इसलिए मैं फिगर जानना चाहता हूं कि पिछले साल कितनी डिमांड थी और कितना दिया था और इस साल कितनी डिमांड थी और कितना दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस में आप यह कैसे पूछ सकते हैं ? आप ने कहा है रिड्यूस्ड कोटा, अगर आप फिगर चाहते थे तो मेंशन करना चाहिए था, इस में आप को विशेष तौर से पूछना चाहिए था ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: मैं ने कोटे का प्रश्न इस में किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा ड्रैस्टिकली रिड्यस्ड, उन्होंने कहा नो ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: इस में बात क्या आई ? वही मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने गलत जवाब दिया है, उन्होंने रिड्यूस किया है, मैं इस को प्रूव करना चाहता हूं । इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): Last year, 1971, we supplied 6.33 lakh tonnes. This year from January to October we supplied 5.32 lakh tonnes. If anything there is an increased tempo of supply to Delhi. Perhaps the hon. Member is referring to the period a few months back when there was a strike. That was a temporary period. That has been got over. As a matter of fact, I am told, there is a glut in the cement market at Delhi today.

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि यहां की डिमांड क्या थी ? आखिर कोटा फिक्स करते हैं तो उस स्टेट की कुछ डिमांड होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि डिमांड क्या थी ? पिछले साल क्या डिमांड थी और इस साल क्या डिमांड थी ?

अध्यक्ष महोदय : आप को पिछले साल और इस साल का पूछना है तो उस के बारे में आप प्रश्न दे दें । आप ने एक जनरल सवाल पूछा तो उस का वह जवाब दे रहे हैं । मैं इस के लिए एलाऊ नहीं कर रहा हूं ।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : मेरा दूसरा प्रश्न है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं सरकार यह कहती है कि मैं ने दिल्ली को और जगहों की अपेक्षा या पिछले साल की अपेक्षा अधिक कोटा दिया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह कर्तव्य है कि नहीं कि नियंत्रित वस्तुएं नियंत्रित मूल्य पर जनता को मिलें, तो इस के सम्बन्ध में इन्होंने क्या व्यवस्था की है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक दिल्ली में सीमेंट की मांग का प्रश्न है दिल्ली में सीमेंट की जो भी मांग रही है, सिवाय जब सीमेंट उद्योग में हड़ताल थी उस के दौरान यहां कठिनाई हुई, उस के अलावा दिल्ली में कोई कठिनाई नहीं हुई । यहां तक कि एशिया 72 के निर्माण कार्य के लिए जो सीमेंट की अतिरिक्त जरूरत थी उस की भी पूरी तरह से पूर्ति की गई और उनको यहां किसी तरह की कोई कमी नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अभी मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई । क्या यह बात सही है कि दिल्ली के जो उपभोक्ता हैं जिन्हें अपने घरों के काम के लिए सीमेंट की आवश्यकता है, उन्हें सरलता से सीमेंट नहीं प्राप्त होती और उन्हें काफी चक्कर डीलर के यहां काटना पड़ता है और अधिक मूल्य दे कर उन्हें सीमेंट लेनी पड़ती है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह बात सही नहीं है । ऐसे लोग जो स्वयं सीमेंट का उपयोग नहीं करते बल्कि सीमेंट ले कर और गलत ढंग से काले बाजार में बेचना चाहते हैं उन लोगों की कार्रवाई की रोकथाम करने के लिए दिल्ली में इस प्रकार का नियंत्रण लागू किया गया है ।

Planning Commission's suggestion on keeping deficit financing within limit

*123. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has suggested to Government to keep the deficit financing within limit in order to keep the prices under control; and

(b) if so, the suggestions made by the Planning Commission and the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Yes, Sir. In the Mid-term Appraisal for the Fourth Five Year Plan it was suggested that deficit financing by Government be kept within strict limits and bank credit to private sector also restricted. It was in the light of this suggestion that deficit financing during the current year was placed at Rs. 250 crores only in contrast to Rs. 700 crores in the preceding year. To attain this objective several measures have since been taken such as substantial tax effort, economy drive, vigorous effort to collect the arrears of income tax, larger market borrowing to mop up surplus liquidity in the economy and elimination of overdrafts by the States. These measures have already begun showing results.

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदय ने इस बात को मंजूर करते हुए बैंक क्रेडिट को प्राइवेट सेक्टर पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात भी कही है अपने स्टेटमेंट में लेकिन उन्होंने यह अपने स्टेटमेंट में नहीं बताया कि इस बारे में क्या कदम उठाये गये ? इसलिए मैं आप के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि बैंक क्रेडिट को प्राइवेट सेक्टर में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उन के द्वारा कोई कदम सजेस्ट किये गये हैं क्या और यदि वह सजेस्ट किये गये हैं तो वह क्या हैं और उन का क्या परिणाम निकला है ?

SHRI MOHAN DHARIA: It is for the Finance Ministry to go into all these details. We have suggested restrictions on all credits; the various steps that we have taken have been enumerated in the statement. If some more details are required by the hon. Member, I would request him to give separate notice.

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि डेफिसिट फाइनेन्सिंग को कन्ट्रोल करने के लिए, कीमतों को कन्ट्रोल करने के लिये यह जरूरी है कि मुद्रास्फिति की वैलासिटी को भी रोका जाय । हम भले ही डेफिसिट फाइनेन्सिंग को कितना ही कन्ट्रोल करें, लेकिन जब तक वैलासिटी को नहीं रोका जायेगा तब तक इन्फलेशन बराबर बना रहेगा और प्राइसेज कन्ट्रोल नहीं हो